अमर उजाला

नई दिल्ली । शुक्रवार, 31 मई 2019

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

हर भारतीय को यह याद होना चाहिए कि इस देश में हर अधिकार मिलेगा पर उसे कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी।
- सरदार पटेल

नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी में मंत्रियों के चयन में योग्यता, विशेषज्ञता और गठबंधन धर्म को जहां तरजीह दी गई है, वहीं अमित शाह और एस जयशंकर का मंत्रिमंडल में शामिल होना भी गौर करने लायक है।

दूसरी पारी की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की पहले से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी जितनी ऐतिहासिक रही है, मोदी के मंत्रिमंडल में अनुभव, पेशेवराना गुण, वरिष्ठता, विशेषज्ञता, जातिगत और लैंगिक संतुलन तथा गठबंधन धर्म के बीच समन्वय साधने की कोशिश भी उतनी ही गौर करने लायक है। हालांकि जदयू और अपना दल के सांसदों की मंत्रिमंडल में मौजूदगी नहीं है, लेकिन एनडीए की विराट जीत के संदर्भ में इस हकीकत को समझा जा सकता है। गौर करने लायक है कि नरेंद्र मोदी की इस दूसरी पारी में संकटमोचक अरुण जेटली नहीं हैं, जिन्होंने मोदी की पहली सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर शानदार काम किया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से इस बार मंत्री पद की जिम्मेदारी लेने की उन्होंने अनिच्छा जताई। कुशल संगठनकर्ता और रणनीतिकार अमित शाह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के महत्व को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। पहली पारी में भाजपा अध्यक्ष के रूप में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले अमित शाह को दूसरी पारी में वरिष्ठ मंत्री के तौर पर सरकार की जिम्मेदारियां संभालते हुए देखा जाएगा। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं। पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल करने का चौंकाने वाला फैसला संभवतः उस खालीपन को भरने की कोशिश ही है। चूंकि भाजपा ने अपने दम पर 303 सीटें जीती हैं, इस कारण उल्लेखनीय जीत हासिल करने वाले कुछ भाजपा नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मसलन, धारवाड़ से चौथी बार जीते प्रह्लाद जोशी को जहां सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा को विराट जीत दिलाने के कारण प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय, चर्चित बेगूसराय सीट से जीतने वाले गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत को दूसरी पारी में प्रोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चुनाव में बड़ी जीत के साथ-साथ चूंकि पांच साल सरकार चलाने की परीक्षा भी बड़ी है, ऐसे में, मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री ने योग्यता को तरजीह दी है। यह इसी का उदाहरण है कि अमृतसर से चुनाव हारने के बावजूद हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

जातिगत अस्मिता की राजनीति का हश्र

मोदी की सफलता के पीछे संघ परिवार द्वारा अस्मिता की राजनीति के अंतर्विरोध को भुनाना है। क्या एक ऐसे विमर्श की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जो जाति खत्म करने की बात सोचे?

विभूति नारायण राय

अस्मिता की राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक दुधारी तलवार की तरह होती है। खास तौर से भारत जैसे बहुधार्मिक या बहुजातीय समाज में आप इससे किसी दीर्घकालीन सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे इसी तरफ इशारा करते हैं। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के परिणामों का विश्लेषण करें, तो इसे समझने में सुविधा होगी। इन्हीं दोनों राज्यों में पिछड़े और दलित की एकता के बल पर पिछले तीन दशकों से मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, कांशीराम और मायावती ने राजनीति की और लंबे समय तक राज्य सत्ता पर कब्जा बनाए रखा।

बीती सदी के सत्तर के दशक में गैर कांग्रेसवाद के साथ ही डॉक्टर लोहिया ने अस्मिता की राजनीति की शुरुआत की थी। उनके 'पिछड़ा पाए सौ में साठ' के नारे में पिछड़ों की राजनीति के अंकुर छिपे थे। पर लोहिया के पिछड़े में आज की पिछड़ी जातियां तो थी हीं, उनमें दलित जातियां भी थीं और स्त्रियां भी। 1967 में जब गैर कांग्रेसवाद की परिकल्पना फलीभूत हुई और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में संविद सरकारें बनीं, तो पिछड़ों की राजनीति का एक युग शुरू हुआ।

उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। शुरू मे वह सिर्फ जाटों के नेता नहीं थे, उनके साथ यादव, कुर्मी, गुर्जर इत्यादि जातियां भी थीं। इतना जरूर था कि उस दौर का पिछड़ा नेतृत्व दलित और महिला विरोधी था। बिहार में कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास जैसे लोगों के हाथ में नेतृत्व आया, जो किसी एक जाति के नहीं, वृहत्तर पिछड़े समाज के नेता थे।

वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होते ही पिछड़ों की एकता और अगड़ी जातियों से उनके हिंसक विरोध का स्तर बढ़ा। पर इसी के साथ पिछड़ों की अलग-अलग जातियों के अपने नेतृत्व खड़े होने शुरू हो गए। पिछड़ों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अगड़ी जाति यादव को उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता मिले। मंदिर आंदोलन के दौरान मुसलमानों के साथ खड़े होकर इन दोनों ने मुस्लिम-यादव दोस्ती की एक मजबूत नींव डाली, जो आज भी चुनावों में कमोबेश उनके काम आ रही है। पर धीरे-धीरे यह नेतृत्व संकीर्ण होता गया। लोहिया से उलट यह नेतृत्व दलित और स्त्री विरोधी था। महिला आरक्षण बिल संसद में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के विरोध के कारण पास नहीं हो सका। दोनों का यादव प्रेम इस हद तक बढ़ गया कि दूसरी पिछड़ी जातियां धीरे-धीरे उनसे छिटकती गईं। पिछड़ों में एक मजबूत सामाजिक और आर्थिक आधार वाली कुर्मी जाति ने बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में सोनेलाल पटेल जैसे प्रभावी नेता खड़े कर दिए। नीतीश जातियों के भारतीय यथार्थ को साधते हुए लगातार बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में संकीर्ण यादव सोच को समझने के लिए एक उदाहरण काफी है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की हैसियत से एक यादव को राज्य लोक सेवा आयोग की कमान सौंपी। उसने अनारक्षित पदों पर तो यादव उम्मीदवार चुने ही, पिछड़ों के लिए आरक्षित पदों पर भी सिर्फ यादव भर दिए। इसलिए जब उसके खिलाफ इलाहाबाद मे छात्र सड़कों पर उतरे, तो उनमें बड़ी संख्या में गैर यादव पिछड़ी जातियों के लड़के-लड़कियां थे। इस चुनाव के दौरान भी जब अखिलेश ने सेना मे अहीर रेजीमेंट खड़ी करने की मांग की, तो निश्चित रूप से दूसरी पिछड़ी जातियों को निराशा ही हुई होगी। कुछ ऐसी ही संकीर्णता का शिकार दलित आंदोलन भी हुआ। अस्सी के दशक में यह सही अर्थों में बहुजन का आंदोलन था।

कांशीराम ने सरकारी कर्मचारियों का संगठन बामसेफ खड़ा किया, जिसमें सभी दलित जातियों का प्रतिनिधित्व था। बहुत से यादव और कुर्मी बुद्धिजीवियों ने बहुजन समाज आंदोलन की सैद्धांतिकी निर्मित की। इस आंदोलन से अपेक्षा थी कि यह डॉ आंबेडकर की सबसे महत्वपूर्ण कामना जातियों के विनाश का प्रयत्न करेगा, पर हुआ बिल्कुल उल्टा ही। कांशीराम और मायावती ने जातियों को नष्ट करने की जगह उन्हें मजबूत ही किया। पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने अलग-अलग जातियों के सम्मेलन किए।

खास तौर से दलित जातियों के नायकों की मूर्तियां मुख्य चौराहों पर लगाई गईं। इनके पीछे छिपी मंशा जातिगत चेतना को हवा देकर बसपा का वोट बैंक बनाना था। मायावती ने स्पष्ट कहा कि बसपा का अध्यक्ष कोई जाटव जाति का व्यक्ति ही हो सकता है। वह भूल गईं कि गैर जाटव दलित जातियां मिलकर जाटवों से अधिक हो जाएंगी। भाजपा ने इसी अंतर्विरोध का लाभ उठाया।

नौकरियों में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ कुछ खास जातियों ने उठाया। अतः सबसे पहले बिहार में दलितों में महादलित और पिछड़ों में अति पिछड़े का विभाजन किया गया। उत्तरी भारत में दलित जातियों में जाटव शिक्षा और सामाजिक / राजनीतिक चेतना मे इसी श्रेणी की दूसरी जातियों से बहुत आगे है, फलस्वरूप नौकरियों का बड़ा हिस्सा उनके खाते में आता है। दलित जातियों में पासी, वाल्मीकि, धोबी, खटिक, मुसहर और दुसाध आदि जाटवों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में पिछड़े हैं। होना यह चाहिए था कि इन्हें भी नेतृत्व और सरकारी नौकरियों में जगह मिलती, पर ऐसा नहीं हुआ। संघ परिवार ने चतुराई से इन अंतर्विरोधों को भुनाया। 2014 के चुनावों तक मुलायम या लालू परिवार समस्त पिछड़ों के नहीं, बल्कि सिर्फ यादवों के नेता रह गए। यह तय हो जाने के बाद कि मुलायम और लालू सिर्फ यादवों के नेता हैं, शेष पिछड़ों को भाजपा में जाने में दिक्कत नहीं हुई। लगभग यही परिदृश्य दलित राजनीति का है। मायावती अब सिर्फ जाटवों की नेता हैं, शेष दलित जातियां भाजपा के खेमे में हैं । 2014 और 2019 के चुनावों में मोदी की सफलता के पीछे यह एक बड़ा कारण है और इससे अस्मिता की राजनीति पर एक नया विमर्श शुरू हो सकता है।

इसकी शुरुआत भाजपा करेगी आरक्षण के लिए पिछड़ों में अति पिछड़े और दलितों में महादलित का बंटवारा करके। क्या लोकतांत्रिक शक्तियों को हस्तक्षेप कर एक ऐसे विमर्श की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जो आंबेडकर के सपने 'जातियों के समूलोच्छेदन' की बात सोचे?

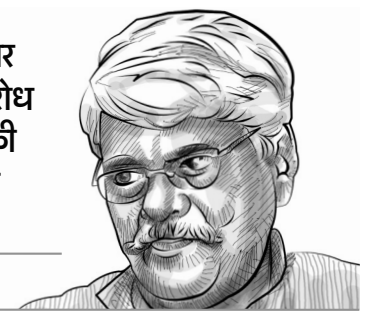

अंतर्ध्वनि

>> आचार्य नरेंद्र देव

मर्यादा को स्वीकार करके ही व्यक्तित्व का विकास संभव है

यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को अमर्यादित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, क्योंकि सब व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। मर्यादा को स्वीकार करके ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। व्यक्ति को यह स्वीकार करना पड़ेगा। यह ठीक है कि व्यक्ति पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, किंतु यह भी सत्य है कि व्यक्ति परिस्थिति को बदलता है। मानव और प्रकृति की एक-दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाए और कानून, परंपरा और रूढ़ि द्वारा उसको स्वतंत्र रीति से सोचने और काम करने का अधिकार न दिया जाए, तो समाज की उन्नति का क्रम बंद हो जाए और मा न वो न ति असंभव हो जाए। इतिहास बताता है कि जिस समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण किया गया और राज्य या समाज की ओर से विचारों का दमन हुआ, उस समाज का ह्रास और पतन हुआ। विचार और संस्था के इतिहास में एक समय आता है, जब वह जड़ और स्थित हो जाती है। परिस्थितियां बदल जाती हैं और वे नए विचारों और नई संस्थाओं की मांग करती हैं। किंतु पुराने विचार और पुरानी संस्थाएं मनुष्य पर ऐसा प्रभाव जमाए रहती हैं कि वह नए सिरे से सोचने को तैयार नहीं होता। अतः समाज के स्वस्थ जीवन के लिए ऐसे केंद्र चाहिए, जहां से पुराने विचारों और संस्थाओं की आलोचना होती रहे और जिनसे नए विचारों के उपक्रम में सहायता मिलती रहे, इसके लिए विचार-विनिमय की स्वतंत्रता अपेक्षित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्यादा को समझे तो व्यक्ति और समष्टि में कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्ति और समष्टि के बीच सामंजस्य का होना जरूरी है। हमारे समाज में विचार-स्वातंत्र्य रहा है। इसके कारण धार्मिक सहिष्णुता भी रही है। इस विचार-स्वातंत्र्य की, जो हमारी सबसे बड़ी निधि है, हमको रक्षा करनी चाहिए और उसकी युग के अनुकूल वृद्धि भी करनी है।

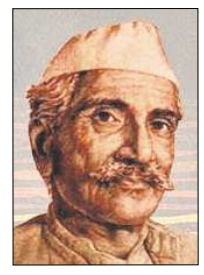

-सुप्रसिद्ध समाजवादी चिंतक

मंजिलें और भी हैं

>> किंजल शाह

जरूरतमंद बच्चों के लिए लगाया भविष्य दांव पर

तब मैं ग्रैजुएशन में थी, जब इस अभियान का विचार आया। मेरे कुछ दोस्त सप्ताहांत में झुग्गियों में जाकर गरीब व जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते थे। उनके साथ मैं भी इसका हिस्सा बन गई। मैं गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूं। 2008 से मैं इन बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही हूं। उस समय लगभग 6-7 दोस्तों के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। हमने गुलबाई टेकरा बस्ती के नगरपालिका स्कूल में जाकर बात की, जिसके बाद हर शनिवार और रविवार दो घंटे तक बच्चों को पढ़ाने की अनुमति मिल गई। मूर्तियां बनाना यहां के लोगों का मुख्य रोजगार है, लेकिन यहां के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हमने वहां जाना शुरू किया, तो पता चला कि ये बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन अवसर न मिलने की वजह से आगे नहीं आ पा रहे थे।

पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ न कुछ कारणों से यह काम रुक-सा गया। मुझे भी नौकरी मिल गई थी, बावजूद इसके मैं हर शनिवार व रविवार इन बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार बस्ती में जाती रही। बस्ती में कई बच्चे ऐसे थे, जो 7वीं-8वीं के बाद स्कूल नहीं गए, जिनमें खासतौर पर कई लड़कियां थीं। इस बारे में मैंने उनके माता-पिता से बात की, तो पता चला कि कहीं सरकारी स्कूल 8वीं तक ही थे, तो कई लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं थे।

छह बच्चों के साथ शुरू हुआ जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का अभियान 600 बच्चों तक पहुंच चुका है।

यह सब देखकर मैंने तय किया कि इन बच्चों को सिर्फ सप्ताहांत नहीं, बल्कि रोज पढ़ाऊंगी। पर नौकरी के साथ उन्हें पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। मेरी समझ में आ चुका था कि मेरी खुशी किसी बड़ी कंपनी के साथ नौकरी करने में नहीं, बल्कि इन गरीब व जरूरतमंद बच्चों का भविष्य सुधारने में है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरा समय इन बच्चों के बीच बिताने लगी।

नौकरी छोड़ने के फैसले पर परिचित और रिश्तेदार बोलते कि, अपना भविष्य खराब करने की क्या जरूरत है, लेकिन मेरे पापा ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, यदि तुमने यह ठान लिया है, तो तुम्हारा अभियान ऐसा हो कि तुम वाकई किसी की जिंदगी बदल सको। मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कुछ रुपये एकत्रित किए और बस्ती के पास ही एक कमरा किराये पर ले लिया। वहां रोज सुबह-शाम दो-दो घंटे मैं इन बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों के दाखिले के लिए भी मैंने फंड इकट्ठा किया। धीरे-धीरे, इनमें बहुत बदलाव आया और इनका स्तर ऊंचा उठा। बच्चों की सफलताओं ने मुझे एहसास कराया कि इस काम को मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकती हूं।

इसके बाद मैंने 'श्वास' नाम से एनजीओ रजिस्टर करवाया। इन बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए मैंने प्रोफेशनल टीचर रखे हैं। छह बच्चों के साथ शुरू हुआ यह अभियान अब 600 बच्चों तक पहुंच चुका है। यह अभियान गुलबाई टेकरा के अलावा कई बस्तियों तक फैल गया है। मेरा ध्यान केवल इन बच्चों की पढ़ाई पर नहीं है, इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि ये हुनर सीखें और आत्म-निर्भर बन सकें। 'श्वास' के लिए दो-तीन कंपनियों के सीएसआर से स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो बहुत से लोग भी बच्चों के लिए डोनेशन देते हैं।

मेरा मानना है कि, आप अपने आस-पास के किसी भी बच्चे को पढ़ाएं और लगातार उसके साथ काम करें। अगर बच्चे की काबिलियत पर भरोसा करें, तो वे जरूर कुछ बेहतर कर सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर उम्मीदें

यह आशा करनी चाहिए कि ऐतिहासिक जनादेश से दोबारा चुनी गई नरेंद्र मोदी की सरकार नई आर्थिक चुनौतियों का रणनीतिपूर्वक मुकाबला कर देश को विकास और खुशहाली की डगर पर आगे बढ़ाने में कामयाब होगी।

जयंतीलाल भंडारी

नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण कर चुके हैं, जिसके बाद आर्थिक मोर्चे पर भारत की धमक और बढ़ने की उम्मीद है। पिछले दिनों स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स ने कहा कि मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार भारत को आर्थिक विकास और सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। इससे आर्थिक नीतिगत स्थिरता बनी रहेगी, विदेशी पूंजी प्रवाह में सुधार आएगा, कारोबार सुगमता बढ़ेगी, कर व्यवस्था ज्यादा सरल बनेगी और निजी खपत व निजी निवेश में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि नई सरकार आगामी पांच साल में देश को आर्थिक शक्ति बनाने की डगर पर आगे बढ़ेगी। वैश्विक सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए नई सरकार मैन्यूफैक्चरिंग, बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र, निर्यात, ई-कॉमर्स, ग्रामीण विकास, भूमि एवं श्रम सुधार और काले धन पर नियंत्रण से लेकर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी और कठोर कदम उठाते हुए दिखाई देगी।

पिछली सरकार के अधूरे एजेंडे को पूरा करने के लिए मोदी-2 सरकार के सामने वैश्विक सुस्ती, कच्चे तेल में तेजी और अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी जैसी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 7.5 फीसदी से घटकर सात फीसदी रह जाने का अनुमान है। ऐसे में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना होगा, कृषि पर ध्यान देना होगा, वैश्विक कारोबार में वृद्धि करनी होगी, उदार टैक्स कानून बनाना होगा, ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुनिश्चित करना होगा, निर्यात में सुधार और विनिर्माण को आगे बढ़ाने की रणनीति बनानी होगी, भूमि एवं श्रम सुधार और डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाना होगा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास, आवास एवं स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं को गतिशील करना होगा।

ब्लूमबर्ग का 2020 के लिए विकास संबंधी अध्ययन आर्थिक विकास में गिरावट का संकेत दे रहा है। ऐसे में ऋण बाजार के दबाव को दूर करना सरकार और रिजर्व बैंक के एजेंडे में होना चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती कर अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार भी नई सरकार के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती होगा। मनरेगा के अलावा स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए मुद्रा योजना को और गतिशील करना होगा और कौशल प्रशिक्षण को ऊंचाइयां देनी होंगी। कृषि कल्याण के लिए नए कदम उठाने होंगे। निजी क्षेत्र को कृषि के साथ जोड़ने के साथ खाद्य प्रसंस्करण का दायरा बढ़ाना होगा और पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना होगा।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी सरकार के लिए चुनौती है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध कड़ा किए जाने से वैश्विक तेल बाजार का संतुलन गड़बड़ा गया है और कीमतें सात महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में, सरकार को बाजार और नए विकल्प तलाशने होंगे। अमेरिका और चीन के बीच गहराते ट्रेड वार के बीच अमेरिका द्वारा भारत पर भी आयात शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका है। भारत से सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को होता है, अतः प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करते हुए एक अच्छा समाधान निकाला जाना चाहिए।

उम्मीद करनी चाहिए कि इस ऐतिहासिक जनादेश से चुनी गई नरेंद्र मोदी की सरकार नई आर्थिक चुनौतियों का रणनीतिपूर्वक मुकाबला कर देश को विकास और खुशहाली की डगर पर आगे बढ़ाने में कामयाब होगी।

खुली खिड़की

आईफोन एक्स एस की कीमत

मूल्य डॉलर की वर्तमान कीमत के आधार पर

आईफोन महंगे मोबाइल फोन में से एक हैं। दुनिया भर में आईफोन को पसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी सबसे अधिक कीमत ब्राजील में है।

स्रोत: डच बैंक/ स्पेक्टेटर इंडेक्स

पाखंडी संत नहीं हैं

सत्संग

देवराहा बाबा परम विरक्त संत थे। वह वृंदावन में यमुना तट पर बनी कुटिया में साधना में लीन रहते थे। अपने दर्शनार्थियों को बाबा हमेशा सदाचार का पालन करने, अपने कर्तव्यों को धर्म मानने और हर क्षण भगवान को याद रखने की प्रेरणा दिया करते थे। एक बार इलाहाबाद से कुछ भक्तजन वृंदावन आए। वह बाबा के पूर्व परिचित थे, इसलिए बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। देवराहा बाबा ने पूछा, बच्चा! प्रतिदिन भगवान की पूजा व उनके नाम का जाप तो पूर्ववत चल रहा है न? उनमें से एक ने कहा, बाबा, हम पहले भगवान की पूजा करते थे, पर अब हमने एक संत को गुरु बना लिया है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक पूजा करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए अब हमारे दर्शन कर समझ लो कि ईश्वर के दर्शन कर रहे हो। उनके आदेश से ही हमने राम-कृष्ण की पूजा छोड़ दी। यह सुन देवराहा बाबा बोले, बेटा तुम कलियुग के प्रभाव में आ गए हो। स्वयंभू अवतार के झांसे में आकर भटक गए हो। जो संत भगवान की पूजा छुड़वाकर अपनी पूजा कराता है और अपने नाम का मंत्र देता है, वह भगवान तो छोड़ो, संत भी नहीं है। सच्चा संत वही है, जो अपने को तुच्छ समझता है। भगवान के भजन का तरीका बताता है। देवराहा बाबा के वचन सुनकर उनकी आंखें खुल गईं। इसके बाद उन्होंने 'ऊं नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करने का संकल्प ले लिया।

-संकलित

हरियाली और रास्ता

कबीर, मां और तोता

एक तोते की कहानी, जिससे जीवन की अहम सीख मिलती है।

कबीर एक दिन दफ्तर से लौटा, तो बहुत नाराज था। मां ने पूछा, 'आज डिनर में क्या खाओगे?' जाने क्यों कबीर उन्हीं पर बरस पड़ा-'आप एक दिन अपने मन से खाना नहीं बना सकतीं क्या? रोज मेरी परीक्षा क्यों लेती हैं।' मां समझ गईं कि यह गुस्सा उसके दफ्तर का है। उन्होंने कहा, 'तुम्हें अपना दफ्तर अच्छा नहीं लगता, तो छोड़ दो। बाहर निकलोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि बाहर है क्या?' कबीर ने कहा, ' इतना आसान होता, तो दो साल पहले ही छोड़ चुका होता।' मां कबीर को एक कहानी सुनाने लगी। एक आदमी पहाड़ों पर सैर करने गया। उसने देखा, चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़, हरे-भरे पेड़ और एकदम ताजा हवा है। वह उन हसीन वादियों का आनंद ले ही रहा था कि एक तेज आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजती हुई उसके कानों में पड़ी। ऐसा लगा, जैसे कोई चीख रहा हो-'आजादी... आजादी।' वह आदमी हैरान होकर ढूंढने लगा कि यह आवाज आ कहां से रही है। काफी ढूंढने के बाद उसे पिंजरे में बंद एक तोता मिला, जो चिल्ला रहा था-'आजादी... आजादी...।' उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पर तोता डरकर अंदर की तरफ भाग गया। आदमी देर तक उसे पुचकारता रहा। पर तोता पिंजरे में बैठा वही राग अलापता रहा-'आजादी... आजादी...।' काफी देर कोशिश के बाद आदमी ने तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर छोड़ दिया। सुबह उस आदमी को फिर वही आवाज सुनाई दी-'आजादी... आजादी...'। पिंजरे के पास जाकर उसने देखा कि दरवाजा खुला है और तोता अंदर बैठकर चिल्ला रहा है-'आजादी... आजादी।' कहानी सुनाकर मां बोलीं-'बेटा, हमारा मन भी इस तोते की तरह है, जो पिंजरे में रहने का अभ्यस्त हो चुका है। पिंजरा छोड़ोगे, तभी तो पता चलेगा कि बाहर दुनिया कितनी खूबसूरत है।

परिस्थिति को अनुकूल बनाने की कोशिश स्वयं करनी चाहिए।